







# कमला हैरिस पर इतना उत्साह क्यों



है, क्योंकि कमला हैरिस भारत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वह अपने लिए और अमेरिका के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वह तो अपने भारतीय मूल को लेकर भी चुनाव उभारा नहीं है। वह खुद को काला मानती हैं और काले अमेरिकियों के साथ ही अपना तादात्य स्थापित करती हैं। हमें उहें बस इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक अमेरिकी

का अमेरिकी चुनाव में खड़ा होता है, तो हम यह मान लेते हैं कि वह भारत के पक्ष में होगा। यह मूर्खतापूर्ण सोच है। सच तो यह है कि वह अमेरिकी हैं। यदि भारत के प्रति उनका रवैया

अच्छा है, तो इसालए नहीं है कि वह भारतीय मूल के हैं, बल्कि इसलिए कि उनको लगता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध अमेरिका के लिए बेहतर सवित होंगे। अमेरिका के चुनाव में किसी भी मूल का अमेरिकी नागरिक जीते, हमें इस बात से पर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि भारत के हितों के साथ अमेरिकी हित मिलते हैं, तो इसमें हमारा फयदा है और यदि ऐसा नहीं है, तो हमारा कोई फयदा नहीं है। इन चुनावों का हमारे लिए इतना ही महत्व होना चाहिए। दूसरी बात, कमला हैरिस पहले भी उच्च पदों पर रह चुकी हैं। यदि आप उनकी तुलना निकी हेली या अन्य भारतीय मूल के लोगों से करें, तो कमला हैरिस ने अपनी से कभी ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके लिए हमें उत्साहित की जरूरत है। हमें यह बात नहीं होगी कि अमेरिका के साथ के रिश्ते यदि बेहतर होते हैं, तो नए नहीं कि कोई भारतीय मूल

का व्याक वहा उच्च पद पर आ है, बल्कि इसलिए कि भारत अमेरिका के हित आपस में मिहाँ हैं कमला हैरिस की उम्मीदवारी लेकर हमें यह देखना पड़ेगा उनकी नीतियां क्या हैं? बहुत से यह मान रहे हैं कि भारत अमेरिका के संबंध एक ऐसे पर पर आ चुके हैं, जहां से उन्हें बोकी तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन कमला हैरिस जिस पार्टी प्रतिनिधित्व करती है, जिस सोच प्रदर्शित करती है और भारत से कई मुद्दों पर उनकी पार्टी की जो है, वह शायद भारत को गवारा होगा, क्योंकि वह भारत के हिनहीं है. कश्मीर, सीएए समेत तभी ऐसे मुद्दे हैं, जहां इनकी और भारत की सोच बिल्कुल अलग है. इन को लेकर दोनों के बीच समस्या होगी. हालांकि चीन और ब्रिटेन समेत आपसी हित से जुड़े मामले को लेकर दोनों के बीच समझौता बेहतर हो सकते हैं. यहां हम आपसी हित, हमारे मतभेदों पर हावी हो जायेंगे कि मतभेदों ज्यादा तबज्जो नहीं दी जायेगी. ऐसा होता है, तो दोनों देशों के फैले

आग बढ़त रहा, परन्तु ये हमारे अत्यधिक संवेदनशील में हस्तक्षेप करने या दबाव कोशिश की, तो दोनों देशों में खटास जरूर आ सकता है। हालांकि यह भी सच है कि या पार्टी जब चुनाव होता है या विपक्ष में हो बहुत-सी बातें बोलता हैं सत्ता में आने के बाद वह ज्यादा तबज्जो नहीं देता। होता है, तब तो भारत और के रिश्ते बेहतरी की तरफ हमारे लिए ज्यादा चिंता वहां की राजनीति में वामपंथी हैं। बिल बिलंटन कार्यकाल में, उनके प्रति रॉबिन राफेल जैसे कुछ शामिल हुए थे, जिन्होंने अमेरिका के रिश्तों में केवल ही पैदा की थी। उन दिनों आतंकवाद चरम पर था पाकिस्तान के पक्ष में थे। हमारे ऊपर काफी दबाव लेकिन उस समय से 3 लगभग 30 वर्ष गुजर चुके हैं के साथ भारत की जो स्थित उसे भारत को अपने ब

द इहान  
त मामलों  
बनाने की  
के संबंध  
कत्ती है.  
कि कोई  
लड़ रहा  
है, तो वे  
, लेकिन  
उसे बहुत  
यदि ऐसा  
अमेरिका  
का जायेंगे.  
का विषय  
शामिल  
के पहले  
गासन में  
ऐसे लोग  
भारत और  
न खटास  
कश्मीर में  
और वह  
उप समय  
बना था,  
जाज तक  
हैं. चीन  
मस्या है,  
लबूते ही

सुलझाना होगा, चीन के समन डट  
कर खड़ा रहना होगा. हमें समझना  
होगा कि कोई भी देश, दूसरे देश की  
लड़ाई नहीं लड़ता. इसके अतिरिक्त,  
चीन को लेकर बहुत-से ऐसे मुद्दे हैं,  
जहां भारत और अमेरिका के आपसी  
हित जुड़े हैं, वहां यदि को-  
ऑफेनेशन और को-ऑपरेशन होता  
है, तो भारत के लिए बेहतर रहेगा.  
अमेरिका के अंदर चीन को लेकर जो  
राय बनी है, वह सरकार बदलने के  
बाद भी शायद नहीं बदलेगी. अमेरिका  
और चीन के बीच के  
संबंध दुबारा वैसे नहीं होंगे, जैसे  
आज से पांच-सात वर्ष पहले थे.  
दूसरी बात, अमेरिका और चीन के  
बीच में तनाव का बढ़ना तथा है,  
लेकिन देखना पड़ेगा कि सरकार  
बदलने पर नवी सरकार इस तनाव  
को किस हद तक लेकर जायेगी. हो  
सकता है कि वह इस तनाव को  
ज्यादा बढ़ावा न दे. यदि ऐसा होता है,  
तो यह चीन के लिए पर्यावाली बात  
होगी, क्योंकि यदि अमेरिका चीन को  
कोने में नहीं धकेलता है, तो चीन  
अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा, जो शायद  
हमारे हित में नहीं होगा, लेकिन अगर  
अमेरिका उसको एक नये शीत युद्ध

म ल जाता ह और आर्थिक, सभ्य  
समेत तमाम तरह के दबाव चीन के  
ऊपर बनाता है, तो वह हमारे हित में  
होगा. माना जा रहा है कि कोरोना के  
बाद की दुनिया में काफी उथल-पुथल  
होगी. पुरानी दुनिया से उलट बिल्कुल  
नयी तरीके की दुनिया उभर कर आ  
रही है. चाहे वह कूटनीति हो,  
राजनीति हो या आर्थिक नीतियां हों,  
उनमें जमीन-आसमान का अंतर  
देखने में आ रहा है. चीन जिस तरह  
से धौंस जमा रहा है और जिस तरीके  
से वह शक्तिशाली होकर उभरा है,  
जाहिर है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय  
सिस्टम में उथल-पुथल पैदा कर दी  
है. आगे चल कर दुनिया शायद दो  
खेमों में बंट जाए. एक ओर चीन,  
दूसरी ओर अमेरिका. यदि चीन के  
साथ हमारे मधुर रिस्ते होते, तो हम  
बीच का रस्ता निकाल कर अपने  
हितों का संरक्षण करते, लेकिन चीन  
ने भारत के साथ जो हरकतें की हैं,  
उसे देखते हुए चीन हमारे लिए एक  
बड़े खतरे के रूप में उभर कर आ  
रहा है. ऐसे में संतुलन बैठाने के लिए  
हमें कहीं-न-कहीं अमेरिका के साथ  
अपने संबंधों को और बेहतर और  
मजबूत करना होगा।

# અન્વાદકાય

## વિવા રોં

**ਪੁਨਾਰ ਜਾ  
ਪੁਨਾਰ ਹੈ**

, ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੈਂਸੇ ਲੁਭਾਵਨੇ, ਜੁਬ  
ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਪਰ ਕਾਗਿਆਂ  
ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆ ਕਾ ਕਿਵੇਂ

जदूल नहीं किया, लाकरन पाता जदूल जहर कर लिया। माझे छाड़ु आरेजेडी के साथ हुए और पिर भाजपा के साथी बन गए। इससे उनके दिन पिर गए। लेकिन बिहार के लोगों के दिन नहीं पिरे। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भूख और इन सबके ऊपर जातिवाद के चंगुल में फंसा बिहार अब कोरोना और बाढ़ की चपेट में आ गया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ऐसे तमाम नेता इन दिनों जोड़-तोड़ की राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्हें इस तरह मसरूफ रखने का काम चुनाव आयोग के तय समय पर चुनाव कराने के फैसले ने किया है। आयोग को लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर कराने की सारी तैयारियां कर ली जाएंगी। महामारी के मद्देनजर जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वे सब उपयोगी किए जाएंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों का ये मानना है कि इस संकटकाल में चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्ताधारियों को शायद अपनी सत्ता किसी की भी जान से अधिक प्यारी है। इसलिए वे भी विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। अब इसके लिए प्रचार कार्य भी शुरू होगा और उम्मीद है कि जिस तरह भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने बिहार में वर्चुअल रैलियां कीं, वैसी ही चुनावी सभाएं वर्चुअली देखने मिलेंगी। इंतजार इस बात का है कि इन आभासी रैलियों में वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होगी या केवल आभासी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे मोदीजी को गलवान में शहीद बिहार रेजीमेंट के जवानों में बिहार की शौर्यगाथा सुनाई पड़ी। जैसे इस बक्त राजनीतिक दलों और मीडिया के लिए बिहार चुनाव के मद्देनजर सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है। इसलिए एक दिन नहीं बीता जब सुशांत सिंह को लेकर कोई सनसनीखेज खुलासा न होता हो। इन लोगों ने मुजफ्फरपुर के आश्रयघर में बच्चियों के साथ हुई ज्यादती या अस्पताल में मरिस्तक बुखार के कारण अकाल मौत का शिकार होते बच्चों के लिए कभी इतनी शिद्दत से इंसाफ की मांग नहीं की। अगर की होती तो आज बिहार के हालात बहुत अलग होते। प्रवासी मजदूरों की व्यथाएं राजनीति की चर्चा के केंद्र में होते।

टेस्टिंग की कमी के कारण या पर्याप्त सावधानियां न बरतने के कारण कोरोना मरीजों की संख्या में जो इजाफ़ हुआ है, उस पर राजनीतिक विमर्श होते। पोस्टरबाजी बिहार चुनाव का एक खास आकर्षण बन गया है। जिसमें कभी जेडीयू लालू प्रसाद के शासनकाल की कमियां दिखाते हुए

# आजादी में विलब अराजकता पढ़ा करता

विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नेहरूजी समेत कांग्रेस नेता सत्ता का भोग करने को उतारले थे। उनका यह कथन पूरी तरह से बेबुनियाद तो ही है, साथ ही इस बात का प्रतीक है कि संबंधित नेता उस समय के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत नहीं हैं। पहली बात यह है कि देश के आजाद होने के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद बनी उसमें कांग्रेस नेताओं के अलावा अनेक गैर-कांग्रेसी भी शामिल किए गए थे। इनमें भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे जो उस समय हिन्दू महासभा के प्रमुख नेता थे। मुखर्जी के अलावा दूसरे अम्बेडकर को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। चूंकि मंत्रिपरिषद का स्वरूप पूरी तरह से राष्ट्रीय था इसलिए यह कहना अनुचित है कि विभाजन इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि नेहरू को सत्ता हासिल करने की जल्दी थी। मूल रूप से जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। इस बीच तत्कालीन वाईसराय माउंट बेटन लंदन गए। वे वहां से 3 जून 1947 को वापिस आए। वापिस आने के तुरंत बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर विभाजन की योजना घोषित की। अगले दिन माउंट बेटन ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि अब ब्रिटेन जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त, 1947 को भारत को आजाद कर देगा। यह भी ज्ञात हुआ था। इस तरह वह स्पष्ट है कि भारत के विभाजन की तिथि का निर्णय ब्रिटेन का था न कि नेहरू व अन्य कांग्रेस नेताओं का। माउंटबेटन की सोच थी चूंकि विभाजन का फैसला हो चुका है इसलिए उसका क्रियान्वयन करने में देरी न हो। यदि देरी होती है तो पूरे देश में साम्राज्यिक हिंसा की आग फैल जाएगी। देरी के चलते लाखों लोग मरे जा सकते हैं। शीघ्र आजाद करने का एक और प्रमुख कारण था। जैसा कि ज्ञात है कि हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन पर सीधी शासन था। वहां कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन ने राजा-महाराजाओं के माध्यम से शासन किया था। अब चूंकि ब्रिटेन अपना शासन समाप्त कर रहा था इसलिए देश के उन हिस्सों की सत्ता हिन्दुस्तान में कांग्रेस को सौंपी जाएगी और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सौंपी जाएगी जहां ब्रिटेन का सीधा शासन था। और जहां तक उन क्षेत्रों का सबाल है जहां राजा-महाराजा और नवाबों का शासन था, 15 अगस्त, 1947 के बाद वे स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि वे स्वतंत्र नहीं रहना चाहते तो वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। यदि वे स्वतंत्र रहने का फैसला करते हैं तो आजाद भारत में सैकड़ों छोटे-छोटे देश अस्तित्व में आ जाएंगे। विभाजन को शीघ्र करने का एक और कारण देश का बालकनाईजेशन रोकना था। ऐसे राजे-रजवाड़ों की संख्या 500 से ज्यादा थीं यदि ये सब आजाद होने का फैसला कर लेते तो भारत एक

A photograph showing several Indian children of different ages and ethnicities waving the Indian national flag. One child in the foreground is jumping high, holding the flagpole. Another child is swinging from a rope attached to the flagpole. The flags are waving in the wind against a bright blue sky.



# दरा म बड़त कसर क गमार सफत

आनेवाला है। देश में अगर कैंसर के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे, तो हिंदुस्तान पूरे विश्व के कैंसर की राजधानी बन जायेगा। सबसे ज्यादा तंबाकू से होनेवाले कैंसर के मामले भारत में दर्ज किये जायेंगे। कैंसर का एक बड़ा कारण जीवनशैली है। अब आइसीएमआर की रिपोर्ट आने के बाद इस बात की जोर-शेरो से चर्चा हो रही है। हालांकि, आंकड़ों से आशिक सहमत हूँ, यह आंकड़ा 12 प्रतिशत की बजाय अधिक हो सकता है। भारत में कैंसर के सभी मामले पारदर्शिता से दर्ज नहीं हो रहे हैं। कस्तों और छोटे शहरों के मामले बड़े शहरों में नहीं पहुँचते। आइसीएमआर की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े बड़े शहरों या कैंसर के निर्धारित अस्पतालों से लिये जाते हैं। छोटे शहरों में कैंसर मरीज ऑपरेशन, कीमो या रेडिएशन लेता है, कई बार तो उचित इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हो जाती है, पर ऐसे मामलों की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा नहीं लग पाता है। तंबाकू कैंसर का एक मुख्य कारण है। रिपोर्ट में इसे 27 प्रतिशत बताया गया है। संभव है कि यह 30 प्रतिशत से ज्यादा हो। तंबाकू की वजह से मृहं, गले, फेफड़े, आदाएं नली ल्लूट कैंसर हो जाएँ हैं।

चिंताजनक है। मिट्टी और जल प्रदूषण की वजह से आजकल सब्जियां और खाद्य पदार्थ विषाक्त हो रहे हैं। सब्जियों में आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड की मात्रा आ रही है, क्योंकि सिंचाई के पानी में फैक्ट्रियों और रसायनों की गंदगी खेतों में पहुंच रही है। अच्छी जीवनशैली, हरी सब्जियां खाने और कोई नशा नहीं करने के बावजूद भी लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। एक बड़ा कारण घर से लेकर वातावरण तक फैला प्लास्टिक भी है। इसमें जीएसए कैंसर का कारण बनता है। आजकल फास्टफूड, पिज्जा, बर्गर आदि खाने का चलन बढ़ रहा है। इनमें सैचूरेटेड फैट होता है। भारतीय खाने की तरह में इसमें फैब्रिक नहीं होता है। इससे आत का कैंसर, महिलाओं में स्तन का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर होने लगा है। मेलामाइन से बननेवाला नकली दूध भी खतरनाक है। तरह-तरह के कैमिकल मानव शरीर में पहुंच रहे हैं। कैंसर धातक बीमारी जरूर है, लेकिन इसे रोका भी जा सकता है। क्या हम तंबाकू को पूरे देश में बंद नहीं कर सकते हैं? तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सुपारी, गुरुखा, जिस भी रूप में तंबाकू उत्पन्न है, उसे तंबाकू बंद उसका विकल्प दलहन या आलू की खेती हो सकती है। तंबाकू की बजाय अन्य जगह निवेश करने की आवश्यकता है। तंबाकू के अर्थशास्त्र को अगर समझें, तो तंबाकू के उत्पादों से जितना रेवेन्यू सरकार को मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा देश को इससे होनेवाली बीमारी पर खर्च करना पड़ता है। यह खर्च चाहे सरकार कर या मरीज अपनी जेब से करे। अगर हम इस बीमारी को रोकने के लिए खर्च को बचा सकते हैं, तो देश को इससे बड़ा फयदा होगा। दूसरा, अगर हम खाद्य पदार्थों में होनेवाली मिलावट को रोक दें या सब्जियों का आदि की टेस्टिंग होने लगे, तो कोई भी ऐसी जगह से उआ कर सब्जियां नहीं बेचेगा, जहां की मिट्टी और पानी जहरीला है। कई छोटे देशों में इसे बड़ा अपराध माना जाता है। यह कानूनी और नैतिक तौर पर भी बड़ा अपराध है। हमारे यहां खाने में मिलावट की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। हम इससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन उपाय नहीं हो रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में कैंसर को रोकने और जागरूकता के लिए कोई अभियान नहीं है और न ही धरातल पर कोई प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

A detailed illustration of a T-lymphocyte (T-cell) interacting with a target cell. The T-cell, characterized by its yellow-orange granular cytoplasm and long, thin protrusions called lymphoplasmin, is shown in the foreground. It is making contact with a target cell, which is depicted as a blue sphere with a distinct purple nucleus. Numerous other similar blue target cells are scattered across a red background, representing a population of infected or abnormal cells. The overall scene illustrates the process of cellular immunology where a specialized immune cell identifies and interacts with specific targets.

हूं कैसर पांडित मरेज का दद्द बहुत हृदय विदारक होता है। वह जीवन बचाने की गुहार लगाता है। कैंसर का ऑपरेशन करके सफलता के बजाय मैं इसको रोकने में अपनी सफलता मानता हूं। इसे रोकने के लिए पेर पर तो काम किया गया है, लेकिन जमीन पर कोई कारगर उपाय नहीं किया गया। कैंसर कारक तत्वों का सेलिक्टिव दृग प्रचाप करने की तबाकू नियत्रण कायरक्रम चलता है, जिसमें आप लोगों से तंबाकू नहीं खाने की बात करते हैं। इससे आसान है कि इसे आप प्रतिबंधित कर दीजिए। साथ ही इसके बचाव के लिए जरूरी है कि नियमित भोजन, उचित नींद, शारीरिक व्यायाम, नशे की वस्तुओं से दूरी यानी आहार, व्यवहार और विचार तीनों ही चीजों में सकलात्मक बदलाव की जरूरत

जग, व्यायाम करें, प्लास्टिक के बर्तनों के इस्तेमाल से बचें, साफ सफई का ध्यान रखें, महिलाओं में सर्वांगिकल कैंसर गंदी के कारण होता है। सही विचार रखें यानी तनाव मुक्त रहें। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर कैंसर का कारण बनता है। आहार, विचार और व्यवहार को सही रखें, तो कैंसर जैसी बीमारी को बिल्कुल गेंहुं सकते हैं।



